

मई दिवस के बहाने

इन्सान काम को एक मजबूरी, एक बोझ के तौर पर लेते हैं। इन्हें कम करने, हल्का करने के मनुष्यों के प्रयासों के सिलसिले को ऊँच-नीच वाली समाज रचनाओं के आगमन ने उलट दिया। मेहनतकशों पर काम का बोझ बढ़ाने की प्रक्रियाएँ आरम्भ हुई।

इस सिलसिले में फैक्ट्री-पद्धति उभरी। हर पल की गणना तथा गति बढ़ाने का अनन्त सिलसिला लिये फैक्ट्री-पद्धति का आदी और अन्त काम है। मौसमों को धत्ता बता कर फैक्ट्री-पद्धति ने बारहों मास काम थोपा। और, यह तो कुख्यात बिजली की करतूत है कि काम की सूर्योदय से सूर्यास्त की सीमाओं को तोड़ दिया गया, लोग दिन ही नहीं बल्कि रात को भी काम में जोत दिये गये हैं।

उत्पादन में फैक्ट्री-पद्धति के उल्लेखनीय दखल को अधिक समय नहीं हुआ है, यही ढाई सौ-क वर्ष ही हुये हैं। फैक्ट्री-पद्धति के संग उत्पादन में मजदूरी-प्रथा उल्लेखनीय बनी। भाप-कोयला द्वारा फैक्ट्री-पद्धति को जमाने के संग मजदूरी-प्रथा का व्यापक विस्तार आरम्भ हुआ। उत्पादन के संग-संग फैक्ट्री-पद्धति, मजदूरी-प्रथा हर क्षेत्र को अपनी जकड़ में लेते गये हैं और ये जीवन को सिकोड़ कर काम के समतुल्य करने पर तुले हैं। खेल-नाच-गाने, विचार-विमर्श, सलाह-मशविरा, फुर्सत, आदर-सत्कार को उल्लेखनीय स्तर तक काम में बदल दिया गया है और फैक्ट्री-पद्धति व दिहाड़ी इन्हें लीलने में लगे हैं। रिटायरमेन्ट को मृत्यु के समान लिया जाने लगा है।

लौटना सिरे से खारिज का

दो सौ-क वर्ष पूर्व दस्तकारों-किसानों और उनमें से नये-नये बने-बनाये मजदूरों की आँखें कुछ मायनों में आज की कदर चौंधियाई नहीं थी। उन्हें अहसास हुआ कि फैक्ट्री-पद्धति जीवन को मजबूरी बनाती है, जीवन को बोझ में बदलती है। उन दस्तकारों-किसानों और नये मजदूरों ने सिरे से फैक्ट्री-पद्धति का विरोध किया। उन्होंने फैक्ट्रियों पर हमले किये, मशीनें तोड़ी और इमारतों में आग लगाई। फैक्ट्रियों को

किलेनुमा बना कर और फाँसी-गोली के जरिये फैक्ट्री-पद्धति के उस प्रारम्भिक विरोध को सिर-माथों पर बैठों ने कुचला।

तत्पश्चात स्वयं फैक्ट्री पर सवाल उठने कम हुये, फैक्ट्री-पद्धति का विरोध मन्द पड़ा। फैक्ट्रियों में राहत, फैक्ट्रियों के जरिये राहत और फैक्ट्रियों पर कब्जे में मुक्ति उल्लेखनीय बने। आठ घण्टे का कार्य-दिवस, गुलाम बनाये देश की स्वतन्त्रता और समाजवादी क्रान्ति को इस सन्दर्भ में प्रतीकों के तौर पर ले सकते हैं।

फैक्ट्री में राहत

फैक्ट्री-पद्धति के शुरुआती दौर से ही पुरुषों के संग स्त्रियाँ व बच्चे फैक्ट्रियों में काम करते रहे हैं। तीव्र से तीव्रतर गति से काम करवाने और रोज अधिक से अधिक समय तक काम करवाने की फैक्ट्री-पद्धति की हवस पर रोकें लगाना मजदूरों के लिये एक अनिवार्य आवश्यकता रही है। बच्चों के काम के घण्टे सीमित करवाना, स्त्रियों के काम के घण्टे कम करवाना पुरुष मजदूरों द्वारा अपने काम के घण्टे कम करवाने का एक अभिन्न अंग था।

इस सिलसिले में सवा सौ वर्ष पहले आठ घण्टे के कार्य-दिवस की डिमाण्ड उठी। एक आदमी को आठ घण्टे काम के बदले में इतने पैसे मिलें कि वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके। परिवार में तब दादा-दादी, पति-पत्नी और उनके 6-7 बच्चे तो होते ही थे। अतः आठ घण्टे के कार्य-दिवस का अर्थ था: एक व्यक्ति को आठ घण्टे काम की इतनी पगार हो कि परिवार के दस सदस्य उस पर पल सकें। परिवार में पुरुष की प्रभुता की वजह से भाषा "आदमी" वाली थी।

टकरावों और दीर्घ खींचा-तान के बाद आज संसार में व्यापक स्तर पर आठ घण्टे की शिफ्ट लागू है। लेकिन, आठ घण्टे की शिफ्ट आठ घण्टे का कार्य-दिवस नहीं होती। इन सौ वर्षों में परिवार सिकुड़ता गया है और दिहाड़ी पर काम करने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती गई है। दादा-दादी को परिवार से खदेड़ दिया है, खदेड़ा जा रहा है और बच्चों को

एस्कोर्ट्स मजदूर: "परमानेन्ट और कैजुअल व ठेकेदारों के जरिये रखे जाते वरकरो की तनखाओं में अन्तर परमानेन्ट वरकरो की जान साँसत में रखता है, नौकरियों के लिये खतरा है।"

आफत के तौर पर लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, एक बच्चे को आदर्श प्रस्तुत किया जा रहा है। वृद्धाश्रमों में मृत्यु का इन्तजार करने वालों की बढ़ती संख्या के संग-संग मजदूरी करते, दिहाड़ी पर काम करते बच्चों और स्त्रियों की संख्या संसार में इन सौ वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ी है तथा इस संख्या में वृद्धि की गति तीव्रतर हो रही है। ऊपर से, शिफ्ट के बाद ओवर टाइम व पार्ट काम व्यापक हुये हैं, और ज्यादा फैल रहे हैं।

परिवार की साइज घटते जाने, परिवार के पालन-पोषण के लिये दिहाड़ी पर काम करने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ते जाने और ८ घण्टे की शिफ्ट के बाद ओवर टाइम, पार्ट टाइम काम के विस्तृत होते जाने की हकीकत हमारे सम्मुख है। इसके मद्देनजर परिवार के पालन-पोषण के लिये कार्य-दिवस आज व्यापक स्तर पर ३०-३२ घण्टे का हो रहा है। पति द्वारा ८ घण्टे की शिफ्ट के बाद ४-८ घण्टे ओवर टाइम-पार्ट टाइम, पत्नी द्वारा ८ घण्टे की शिफ्ट के बाद ४ घण्टे ओवर टाइम, बच्चों द्वारा दिहाड़ी पर काम, दिन आज भी बेशक २४ घण्टे का ही है लेकिन १८८० की ८ घण्टे के कार्य-दिवस की डिमाण्ड आज ३२ घण्टे के कार्य-दिवस की वास्तविकता बन गई है, बन रही है। कार्य की गति में लगातार वृद्धि के साथ-साथ यह उल्टी गंगा बही है।

कार्य-दिवस के लम्बा होते जाने की यह करामत प्रतिनिधि-आधारित कदमों व संगठनों (ट्रेड यूनियनों, संसदीय पार्टियों) के अनथक प्रयासों का परिणाम है।

और, कार्य की तीव्रता पर लीडरी द्वारा ऐसे ब्रेक इन सौ वर्ष में लगे हैं कि कार्य की गति इलेक्ट्रॉनिक रफ्तार की हो गई है। नौकरी की सुरक्षा की बात तक करना आज अटपटा लगने लगा है। ... यह है फैक्ट्री में राहत के परिणाम!

फैक्ट्री के जरिये राहत

इलाके में फैक्ट्रियाँ नहीं होने अथवा कम होने को इलाके में लोगों की बदहाली का कारण बताने का चलन थमा नहीं है। क्षेत्र में फैक्ट्रियों का जाल बिछाने को क्षेत्र के लोगों की खुशहाली का नुस्खा (बाकी पेज चार पर)

खतों-पत्रों से

★ यहाँ पर तो हर स्तर का सामना करना पड़ रहा है। जाति-बिरादरी, रिश्तेदारी, गाँव के पड़ोसी, यह सब सिर्फ नाम के हैं। दुकान के मामले में तो मैं बहुत ही परेशानी महसूस करता हूँ। प्रातः 7 बजे से साँय 8 बजे तक जैसे किसी अमूल्य वस्तु की रखवाली में तैनात किया गया हूँ। सावधानी अतिरिक्त है। जोड़-घटाना, कम-ज्यादा, गुणा-भाग। दिमागी सन्तुलन को ठीक रखना। बोलचाल की भाषा में बनावटी का समावेश करना बहुत ही कठिन लगता है।
.....थोड़ा-सा रोटी का माध्यम

—प्यारे लाल, प्रतापगढ़

★ बँटवारा राजनीति का प्रिय एवं आवश्यक अस्त्र है। बँटने वालों तथा बाँटने वालों, दोनों का क्षणिक लाभ होता है, पर प्रकारान्तर से यही तथ्य सामने आता है कि पुराने बँटे हुये वर्ग को फिर से बाँटा जाये, तभी राजनीति प्रसन्न रह सकती है। यह अन्तहीन सिलसिला है।...

.... मजदूरों की.... हालत... देखकर मन विचलित होने लगता है; और फिर यही कह उठता हूँ—

भीख भी मिलती नहीं है, माँगने से आजकल हक भला कैसे मिलेगा माँगने से दोस्तो!

— राजेन्द्र, लखनऊ

★ कुटिलता ऊँच-नीच वाली समाज व्यवस्था के चरित्र में है। सिर-माथों पर बैठने के लिये साम-दाम-दण्ड-भेद एक अनिवार्यता है। चाणक्य-कौटिल्य ने ढाई-क हजार वर्ष पूर्व इसे सूत्रबद्ध किया.... यह अक्षरक्षः सत्य है जिसे आज भी दबे, कुचलों, शोषितों-पीड़ितों के प्रति अपनाया जा रहा है।

... समाज में पनप रहा असंतोष और हिंसक व्यवहार ... से कुनबे-खानदान की समरसता तक चौपट हो गयी है।

... कब यह अव्यवस्था समाप्त होगी !!!

— बाबू लाल, मन्दसौर

★ यह देख कर सुखद आश्चर्य हुआ कि फमस के तीन-चार अंकों में चिंतन, विचार-विमर्श के मौलिक, बुनियादी व सामयिक मुद्दे उठाये जा रहे हैं। ... भाषा थोड़ी अटपटी है, जिससे विचार को, व्यवस्थित ढंग से, समझने में कठिनाई होती है। अतः इस पर ध्यान दें। ...

— मदन मोहन, रतलाम

(नोट : “अहिंसक समाज रचना” का वह अंक जिसमें श्री मदन मोहन के विद्यालय के बारे में विचार थे वह एक मित्र को पढ़ने को दिया था और फिर मिला नहीं इसलिये उसके अंश हम यहाँ नहीं दे पा रहे।)

डाक पता : मजदूर लाइब्रेरी,
आटोपिन झुग्गी,
एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001

और बातें यह भी

मेल्लो प्रिसिजन मजदूर : “प्लॉट 3 सैक्टर-27 सी स्थित फैक्ट्री में हम कम्पनी के डायरेक्टर को अपना हितैषी मानते थे, उन्हें मजदूरों का हमदर्द मानते थे। साहब के बड़ा अच्छा होने के किस्से फैक्ट्री में चलते रहते थे। जून 2001 में तीन वर्षीय समझौते के वक्त साहब के हालात के रोने-धोने पर हम पिघल गये और बोनस के प्रश्न को भी बाद के लिये छोड़ दिया। साहब पर हमें पूरा विश्वास था। हर वर्ष हमें दिवाली पर 20 प्रतिशत बोनस मिलता था लेकिन वह बीती दिवाली के समय नहीं दिया। अब अप्रैल में आ कर हमें बोनस दिया है और वह भी मात्र 10 प्रतिशत! साहबों के अच्छा होने की बातें किस्सों में ही होती हैं और इन पर विश्वास करना तो धोखे को निमन्त्रण देना है।”

स्वास्तिक इन्टरप्राइज वरकर : “अजीब कम्पनी है, छुट्टी ले कर घर जाते हैं तब हमारे किये हुये काम का वेतन भी नहीं देती। घर से लौटने पर पैसे देते हैं। इधर फरवरी में किये ओवर टाइम के पैसे हमें आज 10 अप्रैल तक नहीं दिये हैं। मार्च का वेतन भी अभी नहीं दिया है।”

एस.पी.एल.मजदूर : “प्लॉट 21-22 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में छापा एक तमाशा रहा। सरकारी अधिकारियों की आवभगत चली और पिछले गेट से मैनेजमेन्ट ने मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। महिला मजदूरों को तो मैनेजमेन्ट मेटाडोरो में भर कर ले गई। फैक्ट्री के अन्दर वही वरकर रहे जिनकी ई.एस.आई. और पी.एफ. थे। जाँच-पड़ताल और कागज-पत्र बटोरने के साथ छापा सम्पन्न हुआ।”

न्यू एलनबरी वरकर : “कम्पनी ने जून 01 में आया महंगाई भत्ता हमें अभी नहीं दिया है। इधर अप्रैल आ गई है और मैनेजमेन्ट कहती है कि जनवरी 02 से देय डी.ए. अभी घोषित ही नहीं हुआ है।”

बेलमैक्स मजदूर : “प्लॉट 125 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में जनवरी के आये डी. ए. के पैसे कम्पनी ने हम 14 वरकरों को छोड़ कर बाकी को दे दिये हैं। इस पर हम मैनेजमेन्ट के पास गये तो साहब बोले कि तुम 14 को डी.ए. के यह पैसे नहीं देंगे, हमारी मर्जी!”

फौजी आटो वरकर : “मार्च में सैक्टर-6

स्थित फैक्ट्री से मशीनें निकाल कर दिल्ली ले गये थे। मजदूर निकालने के लिये मैनेजमेन्ट ने वह ड्रामा किया था। मशीनें वापस फरीदाबाद ले आये हैं और नई भर्ती करके फैक्ट्री में उत्पादन शुरू कर दिया है। भर्ती ऐसी करते हैं कि तनखा नहीं बताते। दो दिन, चार दिन, आठ दिन काम करवा कर निकाल देते हैं और पैसा एक नहीं देते। छह लड़कियों के भी आठ-आठ दिन के पैसे नहीं दिये और उन्हें निकाल दिया।”

कृष्णा ट्रिम्स मजदूर : “प्लॉट 77 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री में हमें वार्षिक बोनस नहीं देते। हमें ई.एस.आई. कार्ड भी नहीं दिये हैं। बीस दिन पर एक दिन वाली छुट्टी, अर्न्ड लीव हमें नहीं देते।”

मुरझाती कलियाँ

गली-गली में कली-कली

फिरती हैं जली-जली

तन-मन सारा दे डाला

फिर भी रोटी नहीं मिली।

कंधे पर है बैग सुहाना

उसमें शीशा एक पुराना

जूती भी हैं टूटी-टूटी

और चुनरी भी सिली-सिली।

गम के मारे थकी-थकी

चलती हैं वो झुकी-झुकी

चेहरे बुझे-बुझे हैं उनके

हैं अभाव में पली-पली।

नौकरियों को जाना है

रोटी का नहीं ठिकाना है

घर में जितनी ईंट लगी हैं

वो भी हैं हिली-हिली।

ज्ञान बहुत है इन कलियों में

फिरती हैं जो इन गलियों में

वक्त के बोझ तले दबी हैं

लगती हैं वो कुली-कुली।

इक तो भीड़ बसों में ज्यादा

और ठीक नहीं लोगों का इरादा

फिर भी मजबूरी में रहती हैं

भीड़ में भी वो घुली-घुली।

पास पड़ोस में चर्चा है

कैसे पूरा खर्चा है

कलियों के दिल में ये बातें भी

रहती हैं खली-खली।

— अजय, ओखला

मजदूर समाचार में साझेदारी के लिये :

★ अपने अनुभव व विचार इसमें छपवा कर चर्चाओं को कुछ और बढ़वाइये। नाम नहीं बताये जाते और अपनी बातें छपवाने के कोई पैसे नहीं लगते।

★ बाँटने के लिये सड़क पर खड़ा होना जरूरी नहीं है। दोस्तों को पढ़वाने के लिये जितनी प्रतियाँ चाहियें उतनी मजदूर लाइब्रेरी से हर महीने 10 तारीख के बाद ले जाइये।

★ बाँटने वाले फ्री में यह करते हैं। सड़क पर मजदूर समाचार लेते समय इच्छा हो तो बेझिझक पैसे दे सकते हैं। रुपये-पैसे की दिक्कत है।

महीने में एक बार छापते हैं, 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

मजबूरी बना जीना, बोझ बना जीना

एस.पी.एल.मजदूर : "प्लॉट 84 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री में महिला मजदूरों को रात नो-साढ़े नो बजे तक कम्पनी रोकती है और फिर उन्हें फैक्ट्री गेट पर छोड़ देती है। फैक्ट्री में 40 महिला मजदूर काम करती हैं और कम्पनी उन्हें सुबह 6 बजे भी काम करने बुला लेती है। महिला हो चाहे पुरुष, सब मजदूरों से रोज 12 घण्टे काम तो लेते ही हैं। फैक्ट्री में 450 वरकर काम करते हैं जिनमें से 200 कम्पनी ने स्वयं भर्ती किये हैं और 250 वरकरों को 10 ठेकेदारों के जरिये रखा है। ठेकेदारों के जरिये भर्ती किये वरकरों को महीने की तनखा 1200 रुपये ही देते हैं - महिला मजदूर भी इसी कैटेगरी में हैं। फैक्ट्री में काम करते आधे से ज्यादा मजदूरों को ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं, प्रोविडेंट फण्ड भी नहीं है।"

कुमार इंजिनियरिंग वर्क्स वरकर : "डी एल एफ एरिया स्थित फैक्ट्री में साहब हर समय सिर पर खड़ा रहता है। खड़े-खड़े चाय पीओ! उत्पादन बहुत ज्यादा थोपरखा है। कारीगरों को सरकारी ग्रेड तक नहीं।"

रुपये महीना तनखा देते हैं। फैक्ट्री में पीने के पानी तक का प्रबन्ध नहीं है - टैंकर से जो पानी मँगाते हैं वह भी खारा होता है।"

एस्कोर्ट्स वरकर : "ट्रैक्टर डिविजन से सब कैजुअल 31 मार्च को निकाल दिये पर ई सी ई एल में हम अब भी काम कर रहे हैं। एस्कोर्ट्स में कैजुअल वरकर के चोट लगने पर कोई सुनवाई नहीं होती। आई.टी.आई. किये कैजुअलों को जनवरी से फस्ट प्लान्ट में 85 रुपये प्रतिदिन देने शुरू किये पर थर्ड प्लान्ट में अब भी 81 रुपये ही दे रहे हैं - साहब लोग सुनते ही नहीं। फैक्ट्री में हमारी आई टी आई ट्रेड का कार्य नहीं देते बल्कि हम से हैल्परि कराते हैं। मैनेजर बहुत ऊट-पटाँग ढँग से बोलता है और सुपरवाइजर एक मिनट भी खड़ा नहीं होने देते - 'काम कर!' रेगुलर वरकर को रात को ओवरटाइम में 30 रुपये अतिरिक्त देते हैं पर हम कैजुअलों को एक पैसा भी नहीं। हमें ओवर टाइम के दौरान खाना बिलकुल नहीं देते - शाम 7 बजे चाय-फैन, रात 11 बजे चाय और फिर रात डेढ़ बजे चाय!"

मक्खियाँ मार कर खाली हाथ लौट आते हैं। क्या करें? कहाँ जायें?"

लेजरान वरकर : "प्लॉट 140 डी एल एफ एरिया स्थित फैक्ट्री में इन दो वर्षों में हमारी 4 महीनों की तनखायें बकाया हो गई हैं। दो वर्ष का बोनस भी हमें नहीं दिया है। भुगतान नहीं किये जाने पर एक फाइनेन्सर एक मशीन ले गया है और बाकी मशीनों को डायरेक्टर बेचने में लगा है। तीन-चार महीनों से काम भी बहुत ढीला-ढाला है। वेतन नहीं दिये जाने की शिकायत हम ने श्रम विभाग में की है। और क्या करें?"

इन्डोपोल मजदूर : "मात्र 1400 रुपये महीना वेतन देते हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते। हमारा प्रोविडेंट फण्ड भी नहीं है।"

आटोपिन वरकर : "इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में अप्रैल-अन्त तक जनवरी माह की तनखा भी वरकरों को नहीं दी गई है। हमारी 4 महीनों की तनखायें तो बकाया हो ही गई हैं, कम्पनी ने 14 महीनों के ओवर टाइम काम की

मैनेजमेन्टों की लगाम

हर कार्यस्थल पर हजारों तार होते हैं; हजारों नट-बोल्ट होते हैं; नालियाँ-सीवर होते हैं; कई-कई ऑपरेशन होते हैं; रात-दिन को लपेटे शिफ्टें होती हैं। इसलिये मैनेजमेन्टों को रोकने-डाटने के लिये मजदूरों के हाथों में कारगर लगाम हैं: * पाँच साल दौड़ने वाली मशीनें छह महीनों में टें बोल दें; * कच्चा माल-तेल-बिजली उत्पादन के लिये आवश्यक मात्रा से डेढी-दुगनी इस्तेमाल हो; * ऑपरेशन उल्टे-पल्टे हो कर क्वालिटी को गंगा नहा दें; * बिजली कभी कड़के, कभी दमके, कभी आँख-मिचौनी करने मक्का-मदीना चली जाये; * अरजेन्ट मचा रखी हो तब ऐसे ब्रेक डाउन हों कि साहबों को हृदय रोग हो जायें।

बिना किसी प्रकार की झिझक के, शान्त मन से, ठन्डे दिमाग से सोच-विचार कर कदम उठाने चाहियें।

जगसन पाल फार्मास्युटिकल मजदूर : "बदरपुर बार्डर स्थित फैक्ट्री में काम बढ़ाने के लिये कम्पनी बहुत तरीके अपना रही है लेकिन हम मजदूरों के लिये लन्च के समय भी चैन की चन्द साँसें लेने का कोई प्रबन्ध नहीं है। कैन्टीन नहीं है और कोई खुली जगह भी नहीं है जहाँ बैठ कर रोटी खा सकें। लन्च समय फैक्ट्री में ही इधर-उधर बैठना पड़ता है। फैक्ट्री में दवाइयाँ बनती हैं और रसायनों की बदबू फैली रहती है। रोटी के संग हमें विभिन्न गैसों की बदबू भी निगलनी पड़ती है।"

हिन्दुस्तान वैक्यूम ग्लास वरकर : "इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में कम्पनी ने 250 परमानेन्ट मजदूर रखे हैं और 12 ठेकेदारों के जरिये हम एक हजार वरकरों को रखा है। कम्पनी ने भट्टियों का काम पीसरेंट पर दिया हुआ है और पैसों के लिये वरकर बहुत ज्यादा खून-पसीना बहाते हैं। तनखा डेढ महीने बाद ही देते हैं।"

मौर्या उद्योग मजदूर : "4-5-6 साल से फैक्ट्री में लगातार काम कर रहे वरकरों को भी ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं। हमारा प्रोविडेंट फण्ड भी नहीं है। हैल्परों को सूखे 1500-1600

अमेटीप मशीन टूल्स मजदूर : "6-7 महीने कचरा-कबाड़ा बेच कर लेट-सेट तनखा दी। इधर फरवरी और मार्च की हमारी तनखायें बकाया हो गई हैं। क्या करें? किसका सिर फोड़ें? अपने ही सिर तोड़ने में लगे हैं।"

मार्शल इंजिनियरिंग वरकर : "सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में कोई वरकर परमानेन्ट नहीं है, हम सब को ठेकेदार के जरिये रखा है। हम में किसी को भी ई एस आई कार्ड नहीं दिया है। हमारा प्रोविडेंट फण्ड भी नहीं है।"

टालब्रोस में अप्रेन्टिस : "आई टी आई ने हमें अप्रेन्टिसशिप के लिये सैक्टर-6 स्थित टालब्रोस इंजिनियरिंग कम्पनी में भेजा है। यहाँ हमें शिक्षण-प्रशिक्षण देने की बजाय मैनेजमेन्ट ने उत्पादन में जोत दिया है। इतना ही नहीं, मैनेजमेन्ट का आदेश है इसलिए हमें रात की शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है। भत्ता हमें आई टी आई देती है और टालब्रोस कम्पनी हमें मुफ्त में मिले मजदूरों की तरह इस्तेमाल कर रही है।"

फर आटो मजदूर : "मथुरा रोड़ स्थित कम्पनी में चार महीनों की तनखायें बकाया होने पर मैनेजमेन्ट ने फैक्ट्री आना ही बन्द कर दिया है। हम रोज ड्युटी जाते हैं और आठ घण्टे

पेमेन्ट भी नहीं की है। और मैनेजमेन्ट की गुण्डागर्दी का यह आलम है कि जबरन ओवर टाइम काम करवाती है। डी.ए. देना बन्द किये यह तीसरा साल हो रहा है। दो साल से हमारी वर्दी भी नहीं दी है। अब फैक्ट्री में मात्र 80 परमानेन्ट मजदूर रह गये हैं। जीना मुश्किल कर दिया है। किससे कहें? क्या करें?"

आर एस पैकेजिंग मजदूर : "17/3 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में हम हैल्परों को 1200 रुपये महीना वेतन ही देते हैं। जायें तो कहाँ जायें?"

गज़ल

सवाल ही सवाल हैं, जवाब कौन देगा
किससे पूछें हाल, जवाब कौन देगा।
श्रम की कीमत पूछते हैं, अजगरों से
व्यर्थ का जंजाल है, जवाब कौन देगा।
हम हैं प्यादे, जिन्दगी शतरंज के
किससे पूछें चाल, जवाब कौन देगा।
सुरक्षा ही असुरक्षित हो गई है
व्यर्थ का बवाल है, जवाब कौन देगा।
हम भागते हैं आगे, मौत पीछे-पीछे
जीने का ख्याल है, जवाब कौन देगा।

- आनन्द, बालाघाट

सरकारी

हरियाणा रोड़वेज ड्राइवर : " 1994 के बाद हरियाणा सरकार ने कोई भी कन्डक्टर अथवा ड्राइवर रेगुलर नहीं किया है। बरसों से हम लगातार काम कर रहे हैं। हमें ड्युटी में ब्रेक नहीं देते। हमें स्पेशल ड्राइवर कहते हैं और इस समय हरियाणा रोड़वेज में हमारी संख्या चार हजार है। पहले हमें 1800 रुपये महीना देते थे और अब 2200 रुपये देते हैं जबकि बिलकुल हमारी ही तरह काम करते रेगुलर ड्राइवर की तनखा दस हजार से ऊपर है। हम से रोज 10-12-14-16 घण्टे ड्युटी ली जाती है पर हमें ओवर टाइम काम का एक पैसा तक हरियाणा रोड़वेज नहीं देती। हम रनिंग स्टाफ में आते हैं और रनिंग स्टाफ के लिये लन्च टाइम का प्रावधान तो रेगुलर ड्राइवरों के लिये भी हरियाणा रोड़वेज के किसी खाते में नहीं है। हम स्पेशल ड्राइवरों की भर्ती डिपोवाइज जनरल मैनेजरों द्वारा की जाती है और बीच में कोई ठेकेदार नहीं है पर सरकार इसे ठेका भर्ती कहती है। हम लगातार ड्युटी करते हैं पर सरकार हमें कानून अनुसार देय अर्न्ड लीव भी नहीं देती। वर्ष में 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर की ही त्यौहारी छुट्टियाँ हमें देते हैं और वे भी बाद में कभी। दिवाली की छुट्टी नहीं, होली की छुट्टी नहीं, फाग के दिन भी हम 'ऑन ड्युटी' होते हैं। सप्ताह में एक दिन रैस्ट किसी भी ड्राइवर को नहीं देते, महीने-डेढ महीने में 4-5 दिन इक्व्हा रैस्ट देते हैं। और, सरकारी दादागिरी की कोई सीमा नहीं है: भर्ती के समय हम से एफिडेविट भरवा लेते हैं कि हम सरकार पर कोई केस नहीं करेंगे, कोई दावा नहीं करेंगे! हालात की मजबूरी है कि इतना कुछ बरदाश्त करना पड़ रहा है। फिर भी, स्पेशल ड्राइवरों का केस तो अदालत में दायर है।"

नये तरीके-नई राहें

जी के एन ड्राइवशाफ्ट मजदूर : " अब तो यह बात बिलकुल साफ है कि हजार वरकरों के हितों का ठेका दस नेताओं के सुपुर्द करना कम्पनियों को खूब फायदा पहुँचाता है। कम्पनियाँ पैसों के बल पर सरकारी अधिकारियों को तो अपनी जेब में रखती ही हैं, वरकरों द्वारा किये वकील को भी कम्पनी अपने साथ कर लेती हैं। अब तो मजदूरों को चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा मजदूर भिन्न-भिन्न तरीकों से कदम उठायें तभी मैनेजमेन्टों की नाक में दम होगा।"

टालब्रोस इंजिनियरिंग वरकर : " सैक्टर-6 में प्लॉट 74 और 75 स्थित प्लान्टों में से बड़ी संख्या में हमारे साथी नौकरी से निकाल दिये गये हैं और कम्पनी ने ठेकेदारों के जरिये नये मजदूर भर्ती कर लिये हैं। पलट कर देखते हैं तो अब समझ में आता है कि बड़े पैमाने पर वरकरों की छँटनी करने की कम्पनी की योजना थी। मैनेजमेन्ट और यूनियन ने ऐसा जाल बिछाया कि हम फँसते गये। हमने हाथ-पैर कम नहीं मारे पर ऐसे में नतीजा हमारे खिलाफ ही गया।"

नोएडा में

एच वी इक्विपमेन्ट मजदूर : " बी-27 सैक्टर-57 नोएडा स्थित फैक्ट्री में हम 100 वरकर काम करते हैं। कम्पनी ने 8 महीनों से हमें तनखायें नहीं दी हैं। नौकरी छोड़ कर हिसाब माँगने पर मैनेजमेन्ट हिसाब भी नहीं देती। दो साल से कम्पनी ने हमारे प्रोविडेंट फण्ड के पैसे जमा नहीं किये हैं। फरीदाबाद जैसे ही हालात नोएडा में हैं। क्या करें?"

रफ़तार जानलेवा है

मई दिवस के बहाने.... (पेज एक का शेष)

फैक्ट्री-पद्धति के पैरोकार आज भी बता रहे हैं। इस सन्दर्भ में क्षेत्रों के तीव्र फैक्ट्रीकरण के लिये नये प्रान्तों, नये देशों की रचना का सिलसिला भी अभी थमा नहीं है। जबकि, फैक्ट्री-पद्धति का विस्तार और मेहनतकशों की हालत बदतर होना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

एक नजर इतिहास पर। उपनिवेशों में फैक्ट्री-पद्धति के अभाव को वहाँ के बाशिन्दों की बदहाली का कारण बताया जाता था। लोगों को खुशहाल बनाने के नाम पर फैक्ट्रियों की स्थापना-विस्तार के वास्ते "गुलाम देशों" को "आजाद" करने की डुगडुगियाँ खूब बजी। मेहनतकशों से कुर्बानियाँ माँगी और ली गई। सौ से ऊपर "देश स्वतन्त्र हुये"। "आजाद भारत" में इन पचास वर्षों में फैक्ट्री-पद्धति का, मजदूरी-प्रथा का तेज गति से व्यापक प्रसार हो रहा है। क्या फैक्ट्रियों के फैलने से राहत मिली है? फैक्ट्री-पद्धति का विस्तार और मेहनतकशों के बद से बदतर होते हालात की हकीकत हमारे सामने है। फैक्ट्री के जरिये राहत के यही फल अन्य "आजाद हुये देशों" में मेहनतकशों के पल्ले पड़े हैं।

फैक्ट्री कब्जे में मुक्ति

काम की अधिकाधिक गति को मुक्ति के लिये आधार तैयार होना लेती और अत्याधिक तीव्र उत्पादन के साधनों पर कब्जे को मुक्ति का क्रान्तिकारी कदम मानती साम्यवादी-समाजवादी धारा कटती-छँटती-जूझती सफलता के उल्लेखनीय पड़ाव पर पहुँची। फैक्ट्रियों पर कब्जे को समाजवादी क्रान्ति ने फैक्ट्री-पद्धति के व्यापक और तीव्र प्रसार का प्रस्थान-बिन्दू बनाया। नतीजा : मजदूरों के लिहाज से सोवियत यूनियन (रूस) और अमरीका में भिन्नता मात्र लेबल की रही।

नई शुरुआत

जीवन के प्रति फैक्ट्री-पद्धति की क्रूरता-घातकता के दृष्टिगत नये सिरे से फैक्ट्री-पद्धति के व्यापक विरोधों की अरजेन्ट आवश्यकता है। फैक्ट्री-पद्धति और इसके आधारों की चीर-फाड़ इसमें सहायक होगी। कुछ बिन्दू हैं :

- अन्य ऊँच-नीच वाली समाज रचनाओं की ही तरह फैक्ट्री-पद्धति आधारित समाज में भी प्रतिनिधि-प्रणाली अन्तर्निहित है-नुमाइन्दे चाहे थोपे हुये हों, चाहे चुने हुये।

- फैक्ट्री में राहत, फैक्ट्री के जरिये राहत, फैक्ट्री कब्जे में मुक्ति के अभियान अहिंसक हों अथवा हिंसक या फिर हिंसा-अहिंसा के मिश्रण वाले, यह सब प्रतिनिधि-लीडर और उनके तानों-बानों द्वारा निर्देशित होते हैं। आदेश अनुसार मजदूर-मेहनतकश हरकत में आयें यह सुनिश्चित करने के लिये तन्त्र आवश्यक होते हैं। ढीले-ढाले-लिजलिजे तन्त्र और चुस्त-कठोर तन्त्र प्रतिनिधि-प्रणाली में संगठन के दो छोर हैं। हुकुम मुताबिक निर्धारित समय पर, निर्धारित ढँग से, निर्धारित कदम उठाये जाना तन्त्र की सफलता के मापदण्ड हैं।

- उन्नीसवीं सदी में और बीसवीं के भी आरम्भिक दशकों में असली प्रतिनिधि और नकली प्रतिनिधि के प्रश्न तीखे वाद-विवाद के विषय रहे हैं। लेकिन फैक्ट्री में राहत, फैक्ट्री के जरिये राहत, फैक्ट्री पर कब्जे में मुक्ति के हश्र देख लेने के बाद यह प्रश्न ही बेमानी हो गये हैं।

- निजी से ज्वाइन्ट स्टॉक से शेयर होल्डिंग की राह कर्ज आधारित बने मालिकाने ने उग्र और नरम, ईमानदार और बेइमान, सुधारवादी और क्रान्तिकारी पार्टियों-लीडरों के बीच भेद मिटा दिये हैं।

- प्रतिनिधि-प्रणाली के नापने के पैमाने आम लोगों के कदमों-प्रयासों के महत्व को ओझल करने का काम करते हैं। जबकि, सामान्य जन की गतिविधियों को प्राथमिक महत्व देना नई राहों का आधार बनता है। इसके लिये प्रभाव-असर मापने के बहुत भिन्न नाप आवश्यक हैं।

- अपनी क्षमता और सुविधा अनुसार प्रत्येक मजदूर द्वारा कौन से कदम उठाने चाहियें और कौन से कदम नहीं उठाने चाहियें? अपने सहकर्मियों के संग हमारे तालमेल कैसे हों? फैक्ट्री-शहर-क्षेत्र-देश की सीमाओं के पार जाते, संसार-व्यापी तालमेलों में कौन से तरीके मजदूरों के माफिक हैं? मन्थन से ही कारगर नये किस्म के संगठित प्रयास तय होंगे। फैक्ट्री-पद्धति के विकल्प में नई समाज रचना के लिये मन्थन में आइये साँझीदार बनें।